

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी- रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 039/2021 (GCMS 2021/39)	दायर दिनांक 19.03.2021	निर्णय दिनांक 16.07.2021
---	---------------------------	-----------------------------

अनवान

उदयलाल पिता भेरा माली जाति माली निवासी भूपालसागर
तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूपालसागर तहसील
भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोंडेंट्स

**-:: प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार भूपालसागर बमामले मिसल
संख्या 17/2021 कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व
अधिनियम निर्णय दिनांक 23.02.2021 ::-**

उपस्थिति :- श्री बीएल पोखरना		अधिवक्ता अपीलांट
श्री भेरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)		अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत एक अपील विरुद्ध रेस्पोंडेंट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 23.02.2021 बमामले मिसल संख्या 17/2021 अनवान सरकार बनाम उदयलाल में अपीलांट को ग्राम भूपालसागर की आराजी नम्बर 1235 को रकबा 0.06 हैक्टर जिसमें 0.02 हैक्टर भूमि पर मकान 0.01 हैक्टर भूमि पर नलकूप एवं 0.03 हैक्टर भूमि पर बाड लगाकर नाजायज कब्जा बताकर अपीलांट को तुरन्त बेदखल कर भूमि तहवील सरकार लिये जाने एवं अपीलांट को 03 माह के साधारण कारावास की सजा दिये जाने का आदेश दिया है जो विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है, अतः यह अपील माननीय



न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है जो समायत न्यायालय श्रीमान है। अपीलांट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई सारवान, विधिपूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न होते हुए एवं पूर्व में किसी आदेश की पालना में अपीलांट को बेदखल किये जाने बाबत तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध न होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को 03 माह की सजा का आदेश दिया है वह विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर निरस्त योग्य है। मकान व नलकूप कई वर्षों पूर्व बना हुआ होकर मौके पर भूमि चरनोट के रूप में कई वर्षों से काम आ रही है। अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बगैर दिनांक 23.02.2021 की पेशी के लिए अपीलांट को तलब किया और उसी दिन अपीलांट के विरुद्ध आदेश जैर अपील यानि दिनांक 23.02.2021 को कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है, इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। नोटिस जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध जारी किया उसमें दिनांक 23.02.2021 को भूपालसागर पर हाजीर होने बाबत तलब किया गया इस नोटिस में पश्चातवर्ती कब्जे के संबंध में अर्थात् पूर्व में कब्जे के संबंध में या पूर्व में बेदखल किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही इस नोटिस में 0.59 हैक्टर पर अनाधिकृत कब्जा बताकर नोटिस दिया है जबकि निर्णय में 0.06 हैक्टर भूमि पर ही नाजायज कब्जा बताकर निर्णय किया है जो नोटिस के विपरीत है इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अन्य तथ्य वक्त बहस अर्ज किये जाएंगे। अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 का है इस कारण यह अपील अब्दर अवधि 30 दिन पेश है जो कि निश्चित समयावधि में होकर माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार की है। अपील निश्चित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर अपीलांट माननीय न्यायालय से सादर प्रार्थना करता है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार भूपालसागर का निर्णय जैर अपील दिनांक 23.02.2021 बमामले मिसल संख्या 17/2021 सरकार बनाम उदयलाल माली निरस्त फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। रेस्पोंडेंट की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर आये। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर का अभिलेख तलब किया गया। इस पर तहसीलदार भूपालसागर के पत्रांक/राजस्व/धारा-91/2021/102 दिनांक 31.03.2021 से उनकी मूल पत्रावली संख्या 017/2021 अनवानी सरकार बनाम उदयलाल पिता भेरा माली निवासी भूपालसागर, अन्तर्गत



धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है।

दिनांक 16.07.2021 को प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया इस पर उभयपक्षकारान की सहमति से प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली की गई। प्रकरण में अपीलांट की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 पर उभयपक्षकारान की सहमति से कार्यवाही ड्रॉप की जाकर मूल अपील पर बहस पत्रावली की गई। अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा की गई बहस अपील को उभयपक्ष सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 23.02.2021 बमामले मिसल संख्या 17/2021 अनवान सरकार बनाम उदयलाल में अपीलांट को ग्राम भूपालसागर की आराजी नम्बर 1235 को रकबा 0.06 हैक्टर जिसमें 0.02 हैक्टर भूमि पर मकान 0.01 हैक्टर भूमि पर नलकूप एवं 0.03 हैक्टर भूमि पर बाड लगाकर नाजायज कब्जा बताकर अपीलांट को तुरन्त बेदखल कर भूमि तहवील सरकार लिये जाने एवं अपीलांट को 03 माह के साधारण कारावास की सजा दिये जाने का आदेश दिया है जो विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है, अतः यह अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है जो समायत न्यायालय श्रीमान है। अपीलांट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बाबत कोई सारवान, विधिपूर्ण साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न होते हुए एवं पूर्व में किसी आदेश की पालना में अपीलांट को बेदखल किये जाने बाबत तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध न होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को 03 माह की सजा का आदेश दिया है वह विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर निरस्त योग्य है। मकान व नलकूप कई वर्षों पूर्व बना हुआ होकर मौके पर भूमि चरनोट के रूप में कई वर्षों से काम आ रही है। अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बगैर दिनांक 23.02.2021 की पेशी के लिए अपीलांट को तलब किया और उसी दिन अपीलांट के विरुद्ध आदेश जैर अपील यानि दिनांक 23.02.2021 को कर दिया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है, इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। इसके जवाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजीयात किस्म चरागाह दर्ज अभिलिखित है एवं अपीलांट का कब्जा बिलानाम भूमि हो कर राजकीय भूमि है जिस पर अपीलांट नियमन की पात्रता नहीं रखती है, जिससे अपीलांट की अपील



सारहीन होकर खारीज किये जाने योग्य है। प्रचलित नियमों के अनुसार चरागाह की भूमि आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज रेकार्ड है जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये एवं अतिक्रमण को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेखों पर दृष्टिपात कराया और बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया जाकर बाद तामील नियमानुसार बाद सुनवाई निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ तहसीलदार, भूपालसागर के निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है। इस पर बहस अपील के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलांट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया जिससे वह अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष नहीं रख सका। पटवारी हल्का की एक मात्र रिपोर्ट पर एक तरफा निर्णय पारित कर दिया। इसके साथ ही नोटिस जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध जारी किया उसमें दिनांक 23.02.2021 को भूपालसागर पर हाजीर होने बाबत तलब किया गया इस नोटिस में पश्चातवर्ती कब्जे के संबंध में अर्थात् पूर्व में कब्जे के संबंध में या पूर्व में बेदखल किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण भी निर्णय जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही इस नोटिस में 0.59 हैक्टर पर अनाधिकृत कब्जा बताकर नोटिस दिया है जबकि निर्णय में 0.06 हैक्टर भूमि पर ही नाजायज कब्जा बताकर निर्णय किया है जो नोटिस के विपरीत है इस कारण आदेश जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को जवाब पेश करने का अवसर चाहा किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब का अवसर दिये बिना ही 3 माह का कारावास व शास्ति से दण्डित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। उक्त निर्णय न्याय, नियम व तथ्यों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट कोई पूर्व अतिक्रमी नहीं है, नहीं अपीलांट ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। इसी ईशतदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। सुनी गई बहस का मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्राप्त अभिलेख का गहनता पूर्वक परिशीलन/अध्ययन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय हेतु रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। हमने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,



1956 की धारा 91 के प्रावधानों का अवलोकन किया। अधिनियम में धारा 91 के तहत व्यवस्था की गई है कि :-

91 Unauthorised occupation of Land - (1) Any person who occupies or continues to occupy any land without lawful monthly shall be regarded as a trespasser and may be summarily evicted there from by the Tehsildar at any time of his motion or upon the application of a local authority at whose disposal such land has been placed, and 69[any crop standing, or any} building or other construction erected. or anything deposited on such land shall, if not removed with in such reasonable time as the Tehsildar may from time to time fix for the purpose, be liable to be forfeited to the State and to be disposed of 1[in the case of any such crop, in the manner he thinks fit and in other cases] as the Collector may direct:

Provided that the Tehsildar may in lieu of ordering the forfeiture of any such building or other construction, order the demolition of the whole or any part thereof.

1[(2) Such trespasser shall further be liable to pay, for 'each agricultural year during the whole or any part where of has been in such unauthorized occupation of the land, a penalty which may extend to fifty times the annual rent, or assessment, as the case may be, for the first act of trespass. In the case of each subsequent ad of trespass, he shall by the order of Tehsildar, be liable to commitment to civic person for a term which may extend to three months and to pay penalty to the extent as aforesaid. The amount of such penalty shall be recovered as an arrear of land revenue, and]

1[(3) Where the trespasser ordered to be committed to civil prison under subsection (2) satisfies the Tehsildar by whom he is ordered to be committed to civil prison that he intends to present an appeal, the Tehsildar shall order that such trespasser be released on his own bond for such periods will afford him sufficient time present the appeal and obtain stay order from the Appellate Court and such order shall so long as he is so released on bond be deemed to be suspended]

(4) In any of the following cases, namely.-

(i) where the trespasser does neither vacate the land not make appearance in response to the notice issue under sub-section (3), or

(ii) where in response to such notice, the trespasser does not vacate the land and makes appearance but-

(a) does not show any such cause, or

(b) makes any representation which is rejected after such inquiry and hearing as may be necessary in the circumstances of the case, the Tehsildar shall, unless, in the case covered by clause (ii) the trespasser under-takes to vacate the land within a week's time- and vacates it whine such time order the removal of the trespasser from such land and shall remove or depute any person, to remove him therefrom and take possession thereof; and if the Tehsildar or the person so deputed is opposed or !impeded in taking possession of such land, the Tehsildar shall apply to a Magistrate having jurisdiction and such Magistrate shall enforce the surrender of the land to the Tehsildar.

(5) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Tehsildar may, in case any such land belongs to the category specified in clause (ii) of the proviso to Section



97, sell it, with the approval of the Sub-Divisional Officer, to the trespasser upon payment by him of the premium therefor at the rate fixed under Section 96 and applicable to such land in addition to the assessment and penalty recoverable from him under sub-section (2) in respect of the whole period of unlawful occupation

1[(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) - (a) whoever occupies any land without lawful authority or, having occupied such land before coming into force of the Rajasthan Land Revenue (Amendment) Act, 1992, fails to remove such occupation within fifteen days from the date of service of a notice in writing calling upon him to do so by the Tehsildar shall, on conviction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to three years and with fine which may extend to twenty thousand rupees; and

(b) whoever, being an employee of the State Government specifically entrusted by an order of the Collector in writing with the duty to stop or prevent an offence punishable under this sub-section wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevent such offence, shall, on conviction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both :
Provided that, in the case of an offence under clause (a), the court may for any adequate or special reason to be mentioned in the judgment impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month :

Provided also that no investigation of an offence under clause (a) of this sub section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police :

Provided further that no court shall take cognizance of an offence under clause (b) except with the previous sanction of the Collector.

विवादित भूमि किस्म चरागाह बीड 1 राजकीय भूमि दर्ज होने से पटवारी हल्का के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार रावतभाटा ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके बेदखली, शास्ति आरोपण किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(44) में अतिक्रमी को परिभाषित किया गया है। उक्त प्रावधान अधिनियम में निम्नानुसार प्रावधित किये गये है।

5(44) "Trespasser"

shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

विवादित आराजीयात आराजी संख्या 1235 किस्म बीड 1 के संबंध में अपीलांत यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट करने में असफल रहा है कि उक्त विवादित आराजीयात में अपीलांत का किसी भी प्रकार से कोई हक अधिकार निहित है, ऐसी स्थिति में अपीलांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(44) के तहत उक्त विवादित आराजीयात का अतिक्रमी है। मकान व नलकूप कई वर्षों पूर्व बना हुआ होकर मौके पर भूमि चरनोट के रूप में कई वर्षों



से काम आ रही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि हल्का पटवारी भूपालसागर द्वारा तहसीलदार भूपालसागर के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार भूपालसागर के पास कार्यवाही हेतु पर्याप्त आधार रहे हैं। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.02.2021 को अप्रार्थी के उपपस्थित रहा। इस पर दिनांक 23.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को अतिक्रमी करार दिया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर विधिक निर्णय पारित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलांत को प्रश्नगत आराजीयात का अतिक्रमी करार दिये जाने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार से विधिक भूल किया जाना प्रतीत नहीं होता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि अपीलांत द्वारा उक्त अतिक्रमण पश्चात्वर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को 3 माह सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है जो उचित प्रतीत नहीं होती है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 में आंशिक हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, एवं अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.02.2021 को संशोधित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रकरण राजस्व अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर द्वारा प्रकरण संख्या 017/2021 अनवानी सरकार बनाम उदयलाल पिता भेरा जाति माली निवासी भूपालसागर, अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2021 को आंशिक रूप से संशोधित किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत उदयलाल पिता भेरा जाति माली निवासी भूपालसागर को दी गई 3 माह सिविल कारावास की सजा को उन्मोचित (Quashed) किया जाता है एवं शेष निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भूपालसागर को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.07.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन)चित्तौड़गढ़

